IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Week-9 & 10 Compilation

DELHI

5B, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi –110005. Landmark: Just 50m from Karol Bagh Metro Station, GATE No. 8 (Next to Croma Store)

Ph:0114167500

BANGALORE

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar Service Road, Vijaynagar, Bangalore 560040. PH: 09035077800 / 7353277800

support@iasbaba.com

www.iasbaba.com

Q.1) भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।
2. सभी राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थानों का निर्माण कर, त्रि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया।
3. 1960 के दशक में ये पंचायती राज संस्थान अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1 और 3

Q.1) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।	यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थानों का निर्माण किया, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में, संख्या के संबंध में, समति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संरचना, कार्य, वित्त और अन्य पर विभिन्नता थी। उदाहरण के लिए, राजस्थान ने त्रि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया जबकि तमिलनाडु ने द्वि-स्तरीय प्रणाली को अपनाया।	1960 के दशक की ये पंचायती राज संस्थाएं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित थीं। अशोक मेहता समिति की नियुक्ति 1977 में हुई थी।

Q.2) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग- IX जोड़ा है।
2. अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायोचित भाग (justiciable part) के अंतर्गत में लाया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत के	अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक

संविधान में एक नया भाग- IX जोड़ा है। यह भाग 'पंचायतों' के रूप में उल्लेखित है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान शामिल हैं।	दर्जा देता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग (justiciable part) के अंतर्गत में लाया है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के अधीन हैं।

Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा का सही विवरण है, जैसा कि 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है?

a) यह एक ऐसा निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क शामिल होते हैं।
b) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
c) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं।
d) यह एक ऐसा निकाय है, जिसमें ग्राम पंचायत के उस क्षेत्र के 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं।

Q.3) Solution (b)

ग्राम सभा एक निकाय है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल एक गाँव की मतदाता सूची में गाँव स्तर पर पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार, यह एक ग्राम सभा है जिसमें एक पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।

Q.4) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सभी स्तरों पर पंचायतों के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
2. सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।	मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से तथा उसके अपने चुने गए सदस्यों में से किया जाएगा। हालाँकि, ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत के अध्यक्ष को इस तरह से चुना जाएगा जैसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है।

Q.5) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार, सीटों के आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई के आरक्षण का प्रावधान है।

2. यह अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
अधिनियम में पंचायत क्षेत्र में कुल आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत (यानी सभी तीन स्तरों पर) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, राज्य विधायिका गांव में पंचायत में अध्यक्ष के कार्यालयों या किसी अन्य स्तर पर एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रदान करेगी।	अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होने का प्रावधान है (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित)। इसके अलावा, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या की न्यूनतम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

Q.6) भारत में पंचायतों के कार्यकाल के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. विघटन के मामले में, किसी भी परिस्थिति में, अपने विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पंचायत का गठन करने के लिए नए चुनाव होने चाहिए।
2. समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित की गई पंचायत का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष के लिए नहीं होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.6) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
अधिनियम प्रत्येक स्तर पर पंचायत को पांच वर्ष के	विघटन के बाद, गठित एक पंचायत की अवधि, पहले की

कार्यकाल के लिए प्रावधान प्रदान करता है। हालांकि, यह अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग हो सकती है। इसके अलावा, पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले (a) पूरे किए जाएंगे; या (b) विघटन के मामले में, इसके विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। लेकिन, जहां **शेष अवधि** (जिसके लिए विघटित पंचायत जारी रही होगी) **छह महीने से कम है**, तो ऐसी अवधि के लिए **नई पंचायत के गठन के लिए कोई चुनाव आयोजित करना आवश्यक नहीं** होगा।	शेष अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके लिए भंग की गई पंचायत जारी रहती, यदि यह भंग नहीं होती। दूसरे शब्दों में, समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित की गई पंचायत पांच वर्ष की पूरी अवधि का आनंद नहीं लेती है, बल्कि शेष अवधि के लिए कार्यालय में ही रहती है।

Q.7) 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक संवैधानिक प्रावधान होने के नाते, अधिनियम भारत के सभी राज्यों में लागू है।
2. संसद यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे, जैसा कि यह निर्दिष्ट कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (d)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**असत्य**
यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में (a) अनुसूचित क्षेत्रों और राज्यों में आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं; (b) मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद मौजूद है; और (c) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। हालाँकि, संसद इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन विस्तारित कर सकती है, जैसे इसे निर्दिष्ट कर सकती हैं।	भारत का राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है।

Q.8) निम्नलिखित में से किसे 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधानों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है?

1. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
2. तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।

3. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।
4. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य

अनिवार्य प्रावधान

1. एक ग्राम या ग्रामों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वोटिंग अधिकार।
6. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण।
8. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें (दोनों सदस्य और चेयरपर्सन) का आरक्षण।
9. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना तथा किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में छह महीने के भीतर नए चुनाव कराना।
10. पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
11. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन।

स्वैच्छिक प्रावधान

1. ग्राम स्तर पर शक्तियों और कार्यों को ग्राम सभा को हस्तांतरण।
2. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण करना।
3. मध्यवर्ती पंचायतों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना या राज्य में मध्यवर्ती पंचायतों न होने की स्थिति में, जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
4. जिला पंचायतों में मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना।
5. अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर आने वाले विभिन्न स्तरों पर संसद के सदस्यों (दोनों सदनों) और राज्य विधानमंडल (दोनों सदनों) को पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।
6. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों (दोनों सदस्यों और अध्यक्षों) का आरक्षण प्रदान करना।
7. पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, ताकि वे स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें (संक्षेप में, उन्हें स्वायत्त निकाय बनाकर)।
8. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए तथा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को पूरा करने के लिए पंचायतों पर शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण;।
9. पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर, शुल्क और फीस, टोल, आदि के लिए अधिकृत करना।
10. एक पंचायत को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोलों और फीस को सौंपना।
11. राज्य के समेकित कोष से पंचायतों को अनुदान देना।
12. पंचायतों के सभी धन संग्रहित करने के लिए धन के गठन का प्रावधान।

Q.9) जिला योजना समिति (District Planning Committee) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करती है।
2. राज्यपाल के पास ऐसी समितियों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है।
3. 74 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, इसके चार- पांचवें (4/5) सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए, तथा समग्र रूप से जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन करेगा।	राज्य विधायिका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकती है: 1. ऐसी समितियों की संरचना; 2. ऐसी समितियों के सदस्यों के चुनाव का तरीका; 3. जिला योजना के संबंध में ऐसी समितियों के कार्य; तथा 4. ऐसी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव का ढंग।	यह अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि जिला योजना समिति के सदस्यों में से चार- पांचवें (4/5) सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने जाने चाहिए। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।

Q.10) नगर निगमों (Municipal Corporations) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये भारत के राष्ट्रपति के आदेश से केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित होते हैं।
2. नगर निगम आयुक्त, निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर और अन्य जैसे बड़े शहरों के प्रशासन के लिए नगर निगम बनाए जाते हैं। वे राज्यों में संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों और भारत के संसद के अधिनियमों द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। राज्य के सभी	नगरपालिका आयुक्त परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार, वह निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और आम तौर पर आईएएस का

नगर निगमों के लिए एक सामान्य अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम हो सकता है।	सदस्य होता है।

Q.11) अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे शहर के प्रशासन के लिए बनाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
चूंकि यह सरकारी गजट में एक अधिसूचना द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के भीतर कार्य करता है, लेकिन अधिनियम के केवल वही प्रावधान इस पर लागू होते हैं जो सरकारी गजट में अधिसूचित किए जाते हैं जिसके द्वारा इसे बनाया जाता है। इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत कार्यान्वयन शक्तियों को भी सौंपा जा सकता है। **यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।**	दो प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र समिति बनाई गई है - औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहा शहर, तथा एक नगर जो अभी तक नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन जिसे अन्यथा राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है।

Q.12) भारत में शहरी स्थानीय शासन (urban local governance) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।
2. सड़कें और पुल, बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगरपालिकाओं के अंतर्गत आते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**

राज्यों ने नामित गतिविधियों या विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कुछ एजेंसियों की स्थापना की है जो 'वैध रूप से' नगर निगमों या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शहरी सरकारों के डोमेन से संबंधित हैं। कुछ ऐसे निकाय हैं: 1. नगर सुधार न्यास। 2. शहरी विकास प्राधिकरण। 3. जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड। 4. हाउसिंग बोर्ड। 5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 6. बिजली आपूर्ति बोर्ड। 7. शहरी परिवहन बोर्ड। ये कार्यात्मक स्थानीय निकाय राज्य विधायिका के एक अधिनियम या एक कार्यकारी संकल्प द्वारा विभागों के रूप में वैधानिक निकायों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। वे स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करते हैं तथा स्थानीय शहरी सरकारों, अर्थात् नगर निगमों या नगर पालिकाओं और अन्य में स्वतंत्र रूप से आवंटित कार्यों को देखते हैं। इस प्रकार, वे स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियां नहीं हैं।	बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के दायरे में निम्नलिखित 18 कार्यात्मक वस्तुएं शामिल हैं: 1. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन; 2. भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन; 3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना; 4. सड़कें और पुल; 5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति; 6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; 7. अग्नि सेवाएं; 8. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन; 9. विकलांग और मानसिक रूप से मंद सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना; 10. स्लम सुधार और उन्नयन; 11. शहरी गरीबी उन्मूलन; 12. शहरी सुविधाओं और पार्क, उद्यान, खेल के मैदान जैसी सुविधाओं का प्रावधान; 13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना; 14. दफन और कब्रगाह मैदान, श्मशान और शवदाह और विद्युतीकृत श्मशान; 15. मवेशी तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम; 16. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े; 17. सार्वजनिक सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं; तथा 18. बूचड़खानों और टेनरियों का नियमन।

Q.13) चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए हैं?

1. मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2. संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट किया है।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

सत्य	असत्य	सत्य
मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उसी तरह और उसी आधार पर उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद नहीं धारण करता है, हालांकि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है।	संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है।	मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है।

Q.14) यूपीएससी (UPSC) से कार्मिक प्रबंधन से संबंधित, निम्नलिखित में से किस मामले पर सलाह ली जाती है?

1. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता।
2. सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित मामले।
3. किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करना।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.14) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**सत्य**	**असत्य**
यूपीएससी द्वारा सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर; पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी में स्थानान्तरण के लिए; तथा स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियों पर परामर्श दिया जाता है। संबंधित विभाग पदोन्नति के लिए सिफारिशें करते हैं और यूपीएससी से अनुरोध करते हैं कि वे इसकी पुष्टि करें।	यूपीएससी द्वारा सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श लिया जाता है।	किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करते समय UPSC से सलाह नहीं ली जाती है।

Q.15) वित्त आयोग (Finance Commission) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
2. राज्यों को अनुदान सहायता देने से संबंधित वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। तदनुसार, संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता निर्दिष्ट की है	वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं तथा इसलिए, सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। राज्यों को अनुदान देने की इसकी सिफारिशों को लागू करना केंद्र सरकार पर निर्भर होता है।

Q.16) अनुसूचित जाति (SC) के राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. किसी भी शिकायत में पूछताछ करते समय उसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं।
2. आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और एंग्लो-इंडियन समुदाय के संबंध में समान कार्यों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
आयोग, जब किसी भी मामले की जांच कर रहा होता है या किसी शिकायत की जांच कर रहा होता है, उसके पास दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट) की सभी शक्तियाँ होती हैं।	2018 तक, आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के संबंध में समान कार्यों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता थी। यह उत्तरदायित्व से 102 वें संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा समाप्त हुआ

Q.17) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. 101 वें संशोधन अधिनियम ने आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
2. सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना 1993 में की गई थी। बाद में, 2018 के 102 वें संशोधन अधिनियम ने आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338-B जोड़ा है।	आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है

Q.18) जीएसटी परिषद के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. केंद्रीय वित्त सचिव, परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
2. परिषद के प्रत्येक निर्णय को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के न्यूनतम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है।
3. केंद्र सरकार के मत का भार, उस बैठक में डाले गए कुल मतों का एक-चौथाई होगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
केंद्रीय राजस्व सचिव, परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।	परिषद के निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। एक बैठक आयोजित करने के लिए परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का आधा भाग कोरम है। परिषद के प्रत्येक निर्णय को बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के न्यूनतम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है।	निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिया जाता है: (i) केंद्र सरकार के मत में उस बैठक में डाले गए कुल मतों का एक तिहाई भारांश होगा। (ii) संयुक्त रूप से राज्य की सभी सरकारों के मतों का भारांश, उस बैठक में डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई होगा।

Q.19) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तों और हटाने के लिए प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।

2. वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के लिए योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तों और हटाने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।	केंद्रीय स्तर पर, आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए, वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

Q.20) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत, आगे किसी कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।
2. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।
3. वह स्थानीय निकायों के खातों का ऑडिट कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
वह अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद, भारत सरकार या किसी भी राज्य के तहत, आगे किसी कार्यालय के लिए पात्र नहीं है।	उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान उसी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, या तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उस प्रभाव को पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।	वह राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों का ऑडिट।

Q.21) नीति आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया है।
2. इसका एक उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
नीति आयोग, भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प (अर्थात, केंद्रीय मंत्रिमंडल) द्वारा स्थापित एक निकाय है। इसलिए, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है।	नीति आयोग के उद्देश्य में शामिल हैं- ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिए तंत्र विकसित करना तथा सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर रूप से व्यवस्थित करना।

Q.22) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं।
2. आयोग का अध्यक्ष, भारत का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
3. सदस्यों में, तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) को मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.22) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	**असत्य**	**सत्य**
आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं।	अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।	सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए तथा तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) को मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

Q.23) निम्नलिखित आयोगों में से किसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पदेन सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
4. राष्ट्रीय महिला आयोग

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 4
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.23) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सात पदेन सदस्य होते हैं - निम्न आयोग के अध्यक्ष

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
- राष्ट्रीय महिला आयोग,
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

Q.24) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
2. अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।	अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

Q.25) राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक SHRC केवल संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
2. केंद्र सरकार, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को SHRCs को दे सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
राज्य मानवाधिकार आयोग केवल **संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची- II) और समवर्ती सूची (सूची- III)** में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।	केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोगों को दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को दे सकती है। **दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** द्वारा निपटाया जाना है।

Q.26) केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राज्य के विधानमंडल के सदस्य को सीआईसी में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को हटाते समय सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य

आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम दस सूचना आयुक्त (वर्तमान में 6) होते हैं। उन्हें कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।	राष्ट्रपति दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। हालाँकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति को इस मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद, हटाने के कारण को बताता है और सलाह देता है, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं।

Q.27) निम्नलिखित में से कौन से निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं?

1. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council)
2. आंचलिक परिषद (Zonal Councils)
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
4. राष्ट्रीय जांच एजेंसी

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1,2 और 4
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.27) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	सत्य	सत्य

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निकाय निम्न हैं:

- अंतर-राज्य परिषद
- आंचलिक परिषद
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Q.28) राज्य सूचना आयोग के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
2. राज्यपाल के पास राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्तियां होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और एक राज्य सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करते, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करते हैं।	राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को कार्यालय से हटा सकता है: (a) यदि उसे दिवालिया माना जाता है; या (b) यदि उसे अपराध का दोषी ठहराया गया है (राज्यपाल की राय में) इसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल है; या (c) यदि वह अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान किए गए रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान संलग्न है; या (d) यदि वह (राज्यपाल की राय में) मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या (e) यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित का अधिग्रहण किया है, जिससे कि उसके आधिकारिक कार्यों को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने की संभावना है। इनके अतिरिक्त, राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी राज्य सूचना आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। हालाँकि, इन मामलों में, राज्यपाल को मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना पड़ता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय, जांच के बाद, हटाने के कारण को बताता है और सलाह देता है, तो राज्यपाल उसे हटा सकते हैं।

Q.29) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CVC की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
2. इसकी स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**सत्य**
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी। इस प्रकार, मूल रूप से CVC न तो संवैधानिक निकाय था	इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा (1962-64) द्वारा की गई थी।

और न ही वैधानिक निकाय। बाद में, 2003 में, संसद ने सीवीसी पर वैधानिक दर्जा देने वाला विधान अधिनियमित बनाया।	

Q.30) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून बनाने में सीवीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होती है।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत संदिग्ध लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए CVC को एक विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.30) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून बनाने में सीवीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होती है।	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत संदिग्ध लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक विशिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

Q.31) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों, आतंक से संबंधित अपराधों तथा गंभीर और संगठित अपराध की जांच करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	**असत्य**
CBI की स्थापना की भ्रष्टाचार पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा संस्तुति की गई थी। इसकी स्थापना	राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और CBI द्वारा जांच किए गए मामलों की प्रकृति में अंतर है। एनआईए का गठन

1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बाद में, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था तथा अब इसे संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है। सीबीआई एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है।	मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य आतंकवादी संबंधित अपराधों की घटनाओं की जांच के लिए 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद किया गया है, जबकि सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और आतंकवाद के अलावा गंभीर और संगठित अपराध की जांच करती है।

Q.32) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) के तहत, भारत में लोकपाल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे संस्थाएँ जो सरकार द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्तपोषित और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान हैं, लोकपाल के प्राधिकार क्षेत्र में आते हैं।
2. लोकपाल को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.32) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को बाहर रखा गया है।	लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए लोकपाल के पास सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देश की शक्ति होगी।

Q.33) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) के तहत, भारत में लोकपाल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतःसंज्ञान (suo motu) कार्यवाही नहीं कर सकता है।
2. लोकपाल के पास शिकायतें दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की सीमा अवधि होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.33) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतःसंज्ञान	लोकपाल के समक्ष शिकायतें दर्ज करने के लिए 7 वर्ष की

(suo motu) कार्यवाही नहीं कर सकता है।	सीमा अवधि होती है।

Q.34) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में हुई थी।
2. एनआईए का क्षेत्राधिकार आतंकी हमलों, साइबर आतंकवाद, जाली नोटों और मानव तस्करी तक विस्तारित है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.34) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
एनआईए को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया था, जिसे 26/11 की घटना के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह देश में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।	एनआईए को बम विस्फोटों, हवाई जहाजों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करने का अधिकार है। 2019 में, एनआईए के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किया गया था। परिणाम स्वरूप, एनआईए को मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराधों की जांच करने, निषिद्ध हथियारों के निर्माण या बिक्री, साइबर-आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों की बिक्री की जाँच करने का भी अधिकार है।

Q.35) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
2. गृह मंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
3. एनडीएमए के कार्यों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना शामिल है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.35) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य

एनडीएमए केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।	**प्रधान मंत्री** एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।	एनडीएमए के कार्यों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना शामिल है।

Q.36) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जिले का कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।
2. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीडीएमए के पदेन सदस्यों में से एक हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.36) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
एक डीडीएमए में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन सात से अधिक नहीं। जिले का कलेक्टर (या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त) डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है।	डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दो जिला स्तरीय अधिकारियों को डीडीएमए के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Q.37) भारत में सहकारी समितियों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
2. एक शीर्ष सहकारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**सत्य**
2011 के 97 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए: 1. इसने सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।	वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह महीने के भीतर प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का ऑडिट किया जाएगा। एक शीर्ष सहकारी समिति के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाएगी।

2. इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर एक नया राज्य नीति का निर्देश सिद्धांत शामिल किया (अनुच्छेद 43-B)। 3. इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा, जिसका शीर्षक "सहकारी समितियां" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) हैं।	

Q.38) संविधान के तहत दिए गए संघ और राज्यों की संपत्ति के बारे में, निम्नलिखित पर विचार करें

1. संघ या राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति के अभ्यास के तहत संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकते हैं।
2. राज्यों के पास प्रादेशिक जल (territorial waters) में मौजूद खनिजों पर अधिकार होता है जबकि महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र में खनिजों के मामले में, केवल संघ का अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
अनुच्छेद 298 के अनुसार, संघ या एक राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति के अभ्यास के तहत संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान कर सकता है।	भारत के समुद्री जल (प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र) के अंतर्गत सभी भूमि, खनिज और मूल्य की अन्य चीजें, **संघ में निहित है।** इसलिए, समुद्र क्षेत्र में एक राज्य इन चीजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता है।

Q.39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संविधान में उन जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाता है।
2. संविधान ने उन व्यक्तियों को परिभाषित किया है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.39) Solution (b)

कथन 1	**कथन 2**
असत्य	**सत्य**
संविधान उन जातियों या जनजातियों को निर्दिष्ट नहीं	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा

करता है जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाता है। यह राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में माना जाए।	वर्गों के मामले के विपरीत, संविधान ने उन व्यक्तियों को परिभाषित किया है जो एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं। तदनुसार, 'एंग्लो-इंडियन का अर्थ, एक व्यक्ति जिसका पिता या पुरुष लाइन में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का है या जो भारत के क्षेत्र के भीतर अधिवासित है और माता-पिता एक ऐसे क्षेत्र के भीतर पैदा हुए थे, जहाँ सामान्य निवासी थे और केवल अस्थायी उद्देश्यों के लिए वहां स्थापित नहीं किए गए थे' हैं।

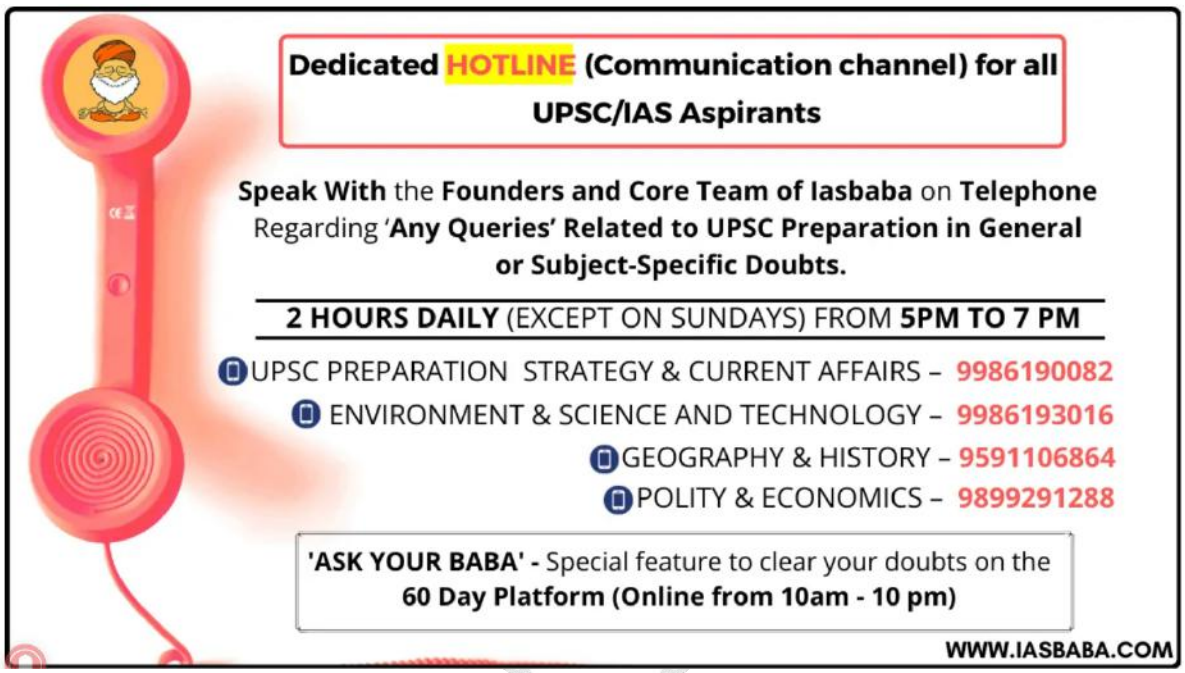

Q.40) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के बारे, में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CAT, भर्ती और इसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा संबंधी मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) का उपयोग करता है।
2. CAT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40) Solution (a)

कथन 1	**कथन 2**
सत्य	**असत्य**
CAT भर्ती और उसके द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के अधीन नागरिक	CAT 1908 के सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ये सिद्धांत CAT को दृष्टिकोण में लचीला रखते हैं।

पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक विस्तारित है। हालांकि, रक्षा बलों के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं हैं।	

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.